several hundreds and thousands of cases are being registered, in more than one-fifth cases, no charge sheet has been filed. The police are delaying the investigation. The cases are delayed for many years without filing any charge sheet. In the absence of charge sheets, the court may not proceed with the trial. Sir, another aspect is the huge pendency of cases. Many of the special cases have not been disposed off. Therefore, ...*(Time-bell-rings)*... the constitution of special courts and fast track courts is required for the offences committed under POCSO Act. Likewise, the Government used to give compensation to the victims. Sir, apart from compensation, rehabilitation should also be there. It was not mentioned in the Act. There was no such provision at all. Sir, the concerned Ministry has to monitor the investigation for speedy disposal of the cases and also charge sheet has to be filed. Unless monitoring is there, the charge sheet may not be filed by the police...*(Time-bell-rings)*... The police have not filed the charge sheet in thousands of cases. Many cases are pending till now, where the offences were committed more than two years back. Sir, I thank you very much for giving me this opportunity.

MESSAGE FROM LOK SABHA

The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

> "In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 24th July, 2019"

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

GOVERNMENT BILL — *Contd.*

The Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019

श्रीमती कान्ता कर्दम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। पहले तो मैं अपनी मंत्री महोदया को बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं बोलने के लिए बहुत कुछ लाई थी और सोचकर भी बहुत कुछ आई थी। मैं अपने प्रधानमंत्री जी और केन्द्रीय महिला एवं बाल

[श्रीमती कान्ता कर्दम]

विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति इरानी जी को धन्यवाद देती हूं, जो इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर आयी हैं, मैं उनको इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देती हूं। आज इस बिल पर यहां दो बजे से चर्चा हो रही है और यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल भी है। सबने ही अपने-अपने हिसाब से बातें रखी हैं। और मुझे सदन से भी उम्मीद है कि यह सदन जरूर इस बिल का समर्थन करेगा, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग भी बहुत दुखी होते हैं, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। यहां कई बार निर्भया कांड का ज़िक्र हुआ। वास्तव में जब निर्भया कांड हुआ था, तो हमारी आंखों के आंसू नहीं रुके थे और जितने भी यहां भाई-बहन और सब लोग बैठे हुए हैं, आपकी आंखों में भी आंसू होंगे और आपको भी बहुत दुख हुआ होगा। देश के हर कोने में - चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई सोशल एक्टिविटी करने वाले हों, चाहे अपने घर के आम लोग हों, गांव हो या शहर हो, सब लोग सड़क पर निकल कर आए थे और इसका विरोध किया था।

महोदय, मैं इतना बताना चाहती हूं कि उसके बाद भी ये अपराध नहीं रुके हैं। आपने देखा होगा कि इतना घिनौना अपराध, गैंगरेप किया गया। उसके बाद भी हाइवे पर इसी तरह का गैंगरेप होता है। जब पूरा परिवार खुशी-खुशी किसी फंक्शन में जाता है, तो रास्ते में गाड़ी रोकी जाती है और उसमें से बच्ची और मां को उतारा जाता है, भाइयों के साथ मारपीट की जाती है और जंगल में ले जाया जाता है। आप सोचिए कि उस मां पर क्या बीती होगी, जब उस छोटी-सी नाबालिग बच्ची क साथ इस तरह का घिनौना अपराध उन्होंने किया। उस मां के ऊपर या उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी, जिस बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है और मां के साथ भी इसी तरह का गैंग रेप हुआ। ये घटनाएं रुकनी चाहिए, इन पर अंकुश लगना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और हम सबको इसका समर्थन भी करना चाहिए। जैसे हमारे परिवार में बच्चे हैं, चाहे वह लड़की है या लड़का है, आज दोनों के लिए ही खतरा बना हुआ है। आज हम न लड़के को भेजकर सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और न ही लड़की को भेजकर। हमें दोनों के लिए ही चिंता बनी रहती है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है और ऐसा कितनी बार देखने को मिला होगा कि लड़के के साथ भी इस तरह का गैंग रेप हुआ। यह बहुत दुखद घटना है। कहीं बेटी झाड़ियों में पाई जा रही हैं, कहीं-कहीं दफ़नाई भी जाती हैं। जैसे यहां पर अभी बात भी आई कि इस तरह के अपराध तो घरों में भी नहीं रुक रहे है। रिश्तेदार, नातेदार और अभी एक बहन कह रह थी कि पिता और बिल्कुल नज़दीक के परिवार के लोग भी इस तरह के अपराध कर रहे हैं, उनके through भी इस तरह के अपराध हो रहे हैं, और फैमिली के लोग ही, घर के लोग ही इन सब चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं। अगर घर का कोई मेम्बर यौन उत्पीड़न में शामिल होता है, तो कह दिया जाता है कि यह घर का सदस्य है, इसके लिए कहीं भी कोई आवाज़ नहीं निकालनी है, बदनामी के डर से कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। यह भी डर होता है कि अगर कहीं आप बोलोगे या फैमिली के लोग भी बोलेंगे, तो उस बच्ची की शादी नहीं हो पाएगी, इस तरह का भी डर होता है।

महोदय, क्या ऐसे घिनौने अपराध करने वाले अपराधियों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? ऐसे अपराधियों को जरूर कड़ा दंड मिलना चाहिए और जब तक बिल में कड़े दंड का प्रावधान नहीं होगा, तब तक ये अपराध नहीं रुकेंगे। इन अपराधों को रोकना बहुत जरुरी है। अभी यहां जो पोर्नोग्राफी की बात हुई, वास्तव में यह भी एक नया शब्द है, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। इसके through भी बच्चों में ये गलत आदतें आती हैं और यह चीज़ गलत है, इसको बढ़ावा देती है। हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वे कहीं भी है, चाहे interior में हैं या शहरों में हैं, जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, विद्यालयों में जो हमारे टीचर्स हैं, जो बहनें टीचर्स हैं या पुरुष टीचर्स हैं, वहां बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में जरूर बताना चाहिए, जिससे कि उन्हें इस बारे में पता लगे। उनको जरूर समझाना और बताना चाहिए कि इस तरह की जो हरकतें करते हैं, उनका विरोध करें। जो गलत हरकत करता है, कोई गलत टच करता है, तो यह गलत है इसके बारे में क्लासों में भी जरूर बताना चाहिए। स्कूलों में चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, दस मिनट या आधे घंटे की चर्चा इस पर जरूर होनी चाहिए और उसके बारे में बच्चों को जरूर बताना चाहिए। महोदय, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 1 जुलाई से बालिका सुरक्षा और जागरूकता के लिए "कवच" नामक अभियान चलाया, जिसमें पुलिस बल, बाल संरक्षण विभाग सहित अन्य संस्थानों ने 10 से 17 वर्ष की बच्चियों से सीधा सम्वाद किया और उन्हें खुद शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने की ट्रेनिंग दी। इस तरह की ट्रेनिंग हर स्टेट में होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी, बच्चों को जागरूक नहीं किया जाएगा, तब तक इसी तरह के अपराध होते रहेंगे। इसी प्रकार मां-बाप का फर्ज़ है कि घर में भी एक दोस्त की तरह, एक friend की तरह बच्चों के साथ पेश आएं, उनके साथ बातचीत करें और उनसे हर बात जानने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है कि बच्ची घर में आकर बताती भी है, लेकिन उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं। मैं यहां सदन में नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन एक टीचर एक बच्ची को पढ़ाने के लिए आता था। वह बच्ची बार-बार कहती थी कि यह मुझे परेशान करता है। उसने कई बार इस बात की शिकायत की, लेकिन उसमें मां-बाप इस बात को नहीं समझे। एक बार उन्हें किसी फंक्शन में जाना था, उस लड़की ने बहुत बार कहा कि मैं आपके साथ जाऊंगी, लेकिन वे कहने लगे कि नहीं बेटा, आपके पेपर हैं, आपको यहीं रहना है। बहुत मित्रता करने के बाद भी वे उसे नहीं लेकर गए। वे इस बात को समझ ही नहीं पाए कि किस चीज़ के लिए वह बोल रही है कि वह टीचर उसे परेशन करता है। उन्हें लगा कि वह पढ़ाई के बारे में बोलती होगी कि वह उसे परेशान कर रहा है। वे उस चीज़ की ओर गए ही नहीं कि एक टीचर, जो उनका जानने वाला है, जो जान-पहचान का टीचर है, जो घर में आकर पढ़ाता है, उस पर उन्हें ऐसी शंका ही नहीं हुई और उसके बाद उस बेटी के साथ रेप होता है। जब वे वापस आते हैं, तो उनकी बेटी बंद कमरे में पायी जाती है और उसके साथ गैंग रेप होता है। वह टीचर अकेला ही नहीं, अपने दोस्तों को बुलाकर उसके साथ गैंग रेप करता है। इसलिए जो टीचर घर में आता है, उसकी गतिविधियों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, उस टीचर पर नज़र रखनी चाहिए कि जो हमारे यहां पढ़ाने आ रहा है या जिसके

[श्रीमती कान्ता कर्दम]

यहां भी हम अपनी बच्ची को भेज रहे हैं, जिसके घर में उसे भेज रहे हैं, उस घर में कौन-कौन रहता है या वह कौन है क्योंकि जब हम उसे किसी के घर में भी भेजते हैं तो टीचर अलग कमरे में पढ़ाते हैं। तो आज - मैं सभी के बारे में नहीं कह रही, लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसी मानसिकता हो गयी है। इसको दूर करने के लिए बिल में संशोधन करके उनके लिए कड़े दंड का प्रावधान होना आवश्यक है। महोदय, 2012 में भी यह बिल आया था और आज इस बिल में संशोधन लाने की जो जरूरत पड़ी, वह इसीलिए पड़ी क्योंकि उसके बाद भी इस तरह की घिनौनी हरकतें लगातार हो रही हैं, जो बंदी होनी चाहिए।

महोदय, अंत में मैं अपनी बहन से एक निवेदन करना चाहती हूं, मेरी एक अपील है कि देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाकर ऐसे मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए कानून में इंतज़ाम किए जाएं।...**(समय की घंटी)**... पॉक्सो एक्ट को ज्यादा प्रभावी बनाकर ऐसे लोगों को निर्धारित समय में सजा दिलाने का प्रावधान करना चाहिए जिससे कि अगर इस तरह की घटना हो रही हो तो वे तुरंत ही जागरूक हो जाएं। कई बार ऐसा होता है कि जब वे ऐसे केसेज़ में थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो भी कोई सुनवाई नहीं होती है।...**(समय की घंटी)**...

महोदय, बहुत सारे interior areas हैं, जहां पर गरीब परिवार के बच्चों के साथ बहुत सी घटनाएं देखने को मिलती हैं। हमारे पास भी बहुत से ऐसे केसेज़ आते हैं कि जो लोग बहुत interior areas में रह रहे होते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि कानून क्या है, क्या नहीं है।...**(समय की घंटी)**... वे इज्ज़त के बारे में सोचकर और समाज के डर से अपना मुंह बंद कर लेते हैं या उस केस को दबाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के घिनौने अपराध बंद होने चाहिए।

महोदय, मैं अपनी बहन स्मृति इरानी जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप पहल करके इस तरह का कठोर दंड देने वाला कानून लेकर आयीं। इस कानून के अंतर्गत उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, इसके लिए मैं अपनी पार्टी को बधाई देती हूं। महोदय, मुझे थोड़ा कम समय मिला, लेकिन फिर भी मुझे समय मिला। मैं स्मृति इरानी जी को और सभी को बधाई देती हूं कि वे इतना अच्छा बिल लेकर आयीं। इससे ऐसे अपराधों पर जरूर पाबंदी लगेगी और उन्हें दंडित करने के लिए जो कानून बनेगा, उससे उन पर अंकुश लगेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, in respect of the Amendment Bill which has been brought forward, I would like to sincerely urge the Minister to send it to a Select Committee. I am making this request first because the Amendment Bill seeks to bring in stringent punishment. It has dealt with only the punishment part of the Act. The POCSO Act was brought and enacted to see that children are protected from child abuse, children get best welfare and welfare in their interest, children get free from child abuse so that they may live a life of dignity, and that is why this Act was enacted in 2012. The amendment which is sought today is fine. I do support the amendment. But it has

gone only to the punishment side. I have heard a lot of Members speak. Many of them have suggested that trial should be in-camera, child should be protected, there should be a timeline, etc. All this is already there in the main Act and there is a need to bring in more amendments for these particular sections. That is why, if this amendment is made more stringent and if we come up with more amendments, it would be better. Why am I saying that? It is because from 2014 to 2016, there has been a record by NCRB, which says that there are almost one lakh and odd cases registered. It is a matter of record. It is also a matter of record that the hon. Supreme Court in this month itself *suo motu* took up the issue of rising child rape cases across the country. The number of cases registered from 1st January to 30th June has crossed 24,000. That is why, when these FIRs are registered, it does speak about the psyche of our society. There should be a separate discussion on where the society is leading to because the whole world is watching that there is a rise in child abuse cases across the country here in India. So, it should be an alarming bell to assess where the society is leading to. That is a separate issue. But when I am talking about an Act, I am talking about law. When I am talking about law, law is hard. Law has to be taken to its logical end in a court which will give justice, which has to be warm. We need to have these inquiries and trials in courts; the purpose of these trials and inquiries is to elicit truth. That is what the hon. apex court says. Why am I saying that? It is because if you see the conviction rate, it is barely 20 per cent. That is what brings us to the Amendment Bill. Why are these provisions not coming in by way of an amendment? Where are those 80 per cent acquittal cases going? If we are talking about children and child abuse, what are we giving them because they have a life ahead? We are talking of several decades which they will be facing in life. We are talking of raw young children who are facing this particular abuse. Many times, the cases are under-reported. The number which we are mentioning is of reported cases. So, you just imagine the plight in the courts when these children are brought to courts before the Magistrate and they have to be kept away from the accused. They do not see the accused so that they do not relive the horrific incident again and again. So, what protection is there? The first thing in a rape case is that the victim is to be taken to the medical fraternity. So, where is that stringent amendment which we are looking for, that there should be a medical team or a team of psychiatrists which will give some kind of solace or a support team which has to be with the child-victim? So, where are these provisions which we need to have? They are in the main Act. So, an amendment is required that there should be a particular frame of timeline

[Dr. Amee Yajnik]

where the trial has to be completed. It has to be in-camera. That is also provided. But where are women-Judges? Where are the courts? Where are POCSO courts? Are these designated courts, which are burdened with other kinds of trials, and have to go on with the same cases? Here, we are talking about child abuse. I think the Minister should look at the particular amendments to be brought into this particular Bill. It has to be sent to a Select Committee in order to get inputs from social workers who give practical support to these victims in time. They end up facing this particular horrific incident till they get justice. Justice is barely 20 per cent. You can imagine 80 per cent of them are at large, moving freely in society. That is where these issues come up. Are we going to give them justice and how are we going to give them justice? The Amendment Bill talks about punishment; yes, life imprisonment or fine or death. We may not go into that. Let that be the prerogative of the court because it depends on the evidence that comes before the courts. But what are we going to do for these children because the Act is mainly meant for the welfare and to give dignity to these children. Where is the rehabilitation package? We can bring it in the Amendment. What are we going to do by way of rehabilitation? What protection are we going to give them? How does this stigma go away? How do you give dignity to them? That needs to be incorporated along with this Amendment. It has gone totally on the punishment side. That is why I would request the hon. Minister to put it before a Select Committee so that inputs from various sections of the country, various stakeholders, people who deal with these kinds of issues with children, do come in the Amendment Bill and it becomes a practically robust and justice delivery Bill for the children. Thank you, Sir.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, I stand here to happily and strongly support this Bill and also express my disappointment that there was an opportunity available in the next two to three months to try and slightly improve this Bill and moreover, use those two-three months, if this Bill had gone to a Select Committee, to create a lot of awareness on this subject. All my esteemed and senior colleagues have spoken and spoken very eruditely about the punishment on offer. I am lucky today because along with the Minister concerned, there is also the Information and Broadcasting Minister who is here. I just want to make one single point. It is not about the punishment, I think, we have all discussed the punishment. Let me just spend three minutes on one point. That point is 'the prevention'. How can we prevent this from happening? Where does it all start? Someone mentioned, it starts on television channels, on Facebook, in

5.00 P.M.

newspapers. It is very clear where it starts. Sir, it starts in your home, in my home and in everybody else's home. It starts in our home because all the cases today, which come to light, they say, 'मामा ने टच किया, काका ने टच किया'। That is how it happens. This is what is availability, and it is for boys and girls. What do we do? We are told, 'ऐसी बात मत करो।' The child actually does not express herself.

The only reason for making this intervention is that I would like and urge more people, especially, in public life, if you have been sexually abused or harassed as a child, please come up and speak about it. The more M.P.s, who come and speak, more actors, more actresses, cricketers and more common people, that is how more families will get encouraged to speak about this. That is what I want to speak about today with a lot of pride, sadness and hurt but, I think, India needs to know, which my family knows, that in a bus at Kolkata, as a thirteen year old, after doing tennis practice, wearing short pant and t-shirt, I got onto a crowded bus. I do not know who it was but my short pant and t-shirt – I was sexually molested in the sense that someone pressed, and I am giving you the explicit details – were reason enough for someone, some unknown man to come and ejaculate at the shorts of this boy. Sir, I did not speak about it for six years, seven years, eight years till I brought it up much later in my life, with my parents. I urge all of us here across political parties, -- the Information and Broadcasting Minister is here; the Minister, who is bringing this Bill, herself has a great track record on television for reaching out to people – we need to use this forum to reach out to people. The more people will talk about it, the more we start talking about it, the more children will be saved. Punishment, very good! Let the courts do. Let us work towards prevention of this heinous crime. Thank you, Sir.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra) : Sir, everyday one opens a newspaper, we read heart-wrecking incidents of children being sexually abused. Our heart bleeds for every child, whether we know them or not know them, in any part of the country. Sir, I stand here to support the Bill that the hon. Minister has mooted. There is introduction of new categories of offences. After all, law-making is a dynamic process. We make laws; we realize that there are gaps and then the Government, at that particular stage, comes up with new provisions and that is exactly what the hon. Minister has done. She has also proposed enhancement of some of the punishments in the existing offences which are also very welcome. I only make reservations about the capital punishment on which I have spoken earlier in the House, and I do not wish to repeat it again at this time in the short time that is at my disposal.

[Shrimati Vandana Chavan]

Sir, I take this opportunity to flag certain concerns about the implementation. After all, law-making is our duty but implementation also has to be done in a proper way to make sure that the laws really stand there to do justice to the people it is meant for. Our hon. Minister is extremely sensitive and I am sure that she will look into these matters. A lot of my colleagues have already mentioned that the conviction rates under the POCSO Act are extremely low. Some of the figures of the crime in India in the NCRB Report are: In 2014, it was 24.6 per cent; in 2015, it was 41.9 per cent and in 2016, it was 29.6 per cent. The conviction rate is extremely low.

My second point is that the pendency is extremely high. If we see the pendency, we see that under Section 28 of the Principal Act, there is a provision of Constitution of Special Courts. Now, in spite of this and in spite of the fact that there is Section 35(2) which says that every trial has to be concluded within a period of one year, Sir, the pendency in 2014 was 95.1 per cent; in 2015 it was 90.2 per cent and in 2016, it was 89 per cent. This is a matter of great concern for all of us. And, as Yajnikji has already said that the Supreme Court has also voiced concern about this and I am sure the hon. Minister will make sure that this is addressed.

I come from a lawyer family. I am a lawyer myself and associated to a group of lawyers even now who deal with cases relating to POCSO. And, therefore, I wish to bring certain points to the notice of the hon. Minister as to the structural compliance which happens in the courts. We have said that Special Courts will have to be constituted. But, the Sessions Courts are given the status of Special Courts. The Sessions Courts continue with their own practice under the Indian Penal Code and only once in a while they become Special Courts under the POCSO.

So, I make an appeal to the hon. Minister that the Special Courts must deal with only and only cases under the POCSO and only then would we see that this pendency is taken care of. Sir, pendency in this case is extremely important if the case is not disposed of in one year, we have to realize that the child has already undergone trauma. We don't want the child to live through trauma. Jaya*ji* has brought a statistics that if the matters as they are going, they would get justice in 2071 which is not expected. So, this is something the hon. ...*(Time Bell rings)*... Sir, I will need to make three more points.

The second point is that the Special Public Prosecutors are also under this Act, Sir, should be women because the Special Public Prosecutors play a very important role.

The Special Public Prosecutor has to make the questions to the Judge and the Judge then puts it to the child so also the defense lawyers. Now, these Special Prosecutors are also not special. They are also doing their additional duty. So, there should be dedicated Special Public Prosecutors and preferably, they should be women because what we need is sensitivity to deal with children and that is something which the hon. Minister should look into.

My third point is that we are dealing with normal courts. If you go to a court, it is something which is overwhelming for us. You see black coats; you see accused; you see Police and imagine a child sitting there all through the day waiting for the Sessions case to get over and then going to the court for his or her case under POCSO. This is really something that we do not wish the child to go through. That is one thing which I feel that the hon. Minister should address.

My fourth point is that the child-friendly atmosphere is what is expected under Section 33 of the Act. Sir, go to a court and you will never find a child-friendly atmosphere. It is totally lacking. The kinds of questions which are to be asked are also like as if they are being asked to an adult and not to a child. Therefore, this also has to be addressed. The identity of a child is very poorly protected. Under this law, the child's name is not to be revealed. But, unfortunately, a study has revealed that Special Courts in Delhi, Maharashtra, Assam, Andhra Pradesh and Karnataka have made no meaningful efforts to ensure that the identity of the victim is protected. This needs to be done with great earnest. Sir, my last two points are these. We need to evaluate and improve our implementation. I have said that we need the Special Courts. Shri Sanjay Raut has said that we have to go to the root as to why so many offences are happening and need to address it at the root itself. The Government gives a lot of advertisements. Why don't we give advertisements in the newspapers to make sure that this deterrent is taken right up to the people? And last but not the least, we need to build a support system for the victims. We have seen victims are not paid the compensatory cost even if they are given the compensatory cost, and, unfortunately, they are left to fend for themselves. I think the Government should take responsibility to make sure that they are given emotional support and also jobs, if necessary.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Now, Shri Rajaram. You have three minutes. Please try to conclude within three minutes.

श्री राजाराम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं "लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019" पर बोलने के लिए बहुजन समाज पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूं। बच्चे देश का भविष्य हैं और बड़े होकर देश की दिशा और दशा, इन दोनों को निश्चित करने

[श्री राजाराम]

की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती हैं, लेकिन आए दिन जिस गति से अपराध बढ़ रहे हैं, वह बहुत चिंता का विषय है। अगर दस सालों का आंकड़ा देखें, तो पिछले दस सालों में नाबालिग बच्चों के ऊपर होने वाले अपराधों में 178.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

महोदय, मुझे कुछ important बातें भी कहनी हैं, लेकिन आप बहुत कम समय सीमा निश्चित कर रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितनी बातें कह सकूं, उतनी कहूं। जो बालक होते हैं, वे अपनी अल्प अवस्था, शारीरिक दुर्बलता तथा जीवन और समाज का अनुभव नहीं होने के कारण आसानी से इनके शिकार हो जाते हैं। उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उससे वे दोनों रूपों में, शारिरिक रूप से और मानसिक रूप से प्रभावित होते हैं। वे शारीरिक रूप से तो प्रभावित होते ही हैं, साथ ही मानसिक रूप से भी प्रभावित हो जाते हैं, जिससे कि उनकी आगे की लाइफ बहुत tough और मुश्किल हो जाती है। ऐसी घड़ी में यह अधिनियम लिंग निरपेक्ष और बालकों के सर्वोत्तम हित और कल्याण से संबंधित है, जिससे कि बालक के अच्छे शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। चूंकि देश में बाल यौन अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुछ कड़े कानूनी कदम उठाए गए हैं, जिससे कि बालक का सुरक्षित, संरक्षित और गौरवपूर्ण बचपन हो।

महोदय, इस विधेयक के खण्ड छः में गुरुतर प्रवेशन, लैंगिक हमले के लिए आजीवन कारावास, मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। यह जो प्रावधान किया गया है, जो कड़ा कानून बनाना गया है, मैं उसके संदर्भ में यह बताना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश में भी कई बार ऐसे कानून बने हैं। अभी फिलहाल में यौन अपराध रोका जाए या बच्चों के साथ दुर्व्यवहार न हो, इसके लिए एक anti-Romeo squad बन गया, लेकिन उसका result क्या रहा? उसका रिज़ल्ट यह रहा कि RTI के तहत ली गई State Crime Records Bureau की रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में रोज बावन महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कानून बना देने से ये अपराध रुक जाएंगे, यह संभव नहीं है। ...**(समय की घंटी)**... इसके लिए भी कुछ विशेष व्यवस्थाएं करनी चाहिए।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इसकी जो धारा 14 खंड (ए) है, इसमें यह लिखा है कि, "जो कोई, अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक का प्रयोजन करेगा..." अगल बालक का प्रयोजन करेगा, mastermind है, लेकिन स्वयं involved नहीं है, वह किसी से प्रयोजन करवाता है, तो उसमें सजा का प्रावधान पांच साल है। और उसी के खण्ड 2 में लिखा है कि अगर वह स्वयं करता है, तब उसके लिए सजा का प्रावधान दस साल या आजीवन है। महोदय, यह थोड़ा-सा असहज है, क्योंकि उसमें बालक affected तो है, जुल्म तो उसके ऊपर हो रहा है, बलात्कार तो उसके हाथ हो रहा है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, वह जब किसी और से करवाता है, तो उसके लिए पांच साल की सजा है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Thank you.

श्री राजाराम : महोदय, कम से कम मेरा सुझाव तो ले लीजिए, ऐसे ही बोलने से तो कोई मतलब पूरा नहीं होगा। अभी तो मैं बिल पर बोला हूं, हमारे एक-दो सुझाव तो ले लीजिए।

मुझे यह कहना है कि क्राइम के मास्टरमाइंड के लिए यह जो अलग-अलग सज़ा निश्चित की गई है, कम से कम इसे बराबर किया जाए, क्योंकि मास्टरमाइंड तो एक वही है। एक तरफ वह दूसरे से क्राइम करवा रहा है और दूसरी तरफ वह स्वयं क्राइम में इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन पहले केस में उसे पांच साल की सज़ा दी गई है और दूसरे केस में आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है।

इसके साथ-साथ मैं और एक-दो सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगा। ऐसे केसेज़ में कानून ऐसा हो, जिसमें अपराधियों को शीघ्र सज़ा मिले। यह मेरा पहला सुझाव है कि इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट खोली जानी चाहिए। मेरा दूसरा सुझाव है कि पीड़ित बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, बच्चों को बार-बार कोर्ट में न जाना पड़े, इसके लिए बच्चों एवं उनके परिवार वालों के लिए परामर्शदाता, समाज सेविका, वकीलों आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हो, वह तुरन्त हो और बंद कमरे में हो। पांचवां, पीड़ित बच्चों के आर्थिक मदद निधि की व्यवस्था होनी चाहिए। एससी/एसटी के बच्चे वैसे भी आर्थिक तौर पर भी बहुत कमजोर होते हैं, साथ ही मानसिक तौर पर भी कमजोर होते हैं, ऐसे में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उनकी सहातया एवं सुरक्षा दोनों की व्यवस्था हो। किशोर न्याय व्यवस्था को और अधिक मज़बूत बनाया जाए, इसके लिए जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए।

महोदय, इस बिल का समर्थन करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि केवल कानून बना देने से यह नहीं रुकेगा।...**(समय की घंटी)**... इस पर निष्ठा और ईमानदारी के साथ अमल भी होना चाहिए, जय हिन्द।

SHRI T.K. RANGARAJAN: Thank you. Next speaker is, Shri Sushil Kumar Gupta. Mr. Gupta, you have three minutes.

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी, क्षेत्र दिल्ली) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बिल के पक्ष में खड़ा हुआ हूं और माननीय मंत्री महोदया के प्रति, POCSO कानून को और सख्त बनाने के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं।

देश के बच्चे कितनी विकट स्थिति से गुज़र रहे हैं, इस बात का अंदाज़ा केवल कुपोषण और अशिक्षा के आंकड़ों से नहीं लगाया जा सकता है। कुछ ऐसे मामले हैं, जहां पर आंकड़े खामोश हो जाते हैं या उनकी आवाज़ इतनी मद्धिम हो जाती है कि कुछ सुनाई ही नहीं देता और यौन शोषण, विशेषकर बच्चों का यौन शोषण एक ऐसा ही मामला है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, बाल यौन शोषण के मामले में पुलिस फोर्स को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को और कोर्ट को और

[श्री सुशील कुमार गुप्ता]

अधिक संवेदनशील बनना होगा। इन केसेज़ को केवल साधारण केस न समझें। रेप पीड़ित बच्चे, महिलाएं और उनके परिवार वालों की जिन्दगी किस हाल से गुज़रती है, यह उनकी आत्मा ही जानती है। आप उसके ऊपर मरहम लगाने का काम करें और पूरी आत्मीयता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ, उन केसेज़ को डील करें। कोर्ट में या पब्लिकली उनसे उल्टे-सीधे क्वेश्चन न पूछे जाएं, ताकि उनकी आत्मा अपने आप को और न झकझोरे।

दिल्ली, यौन अपराधों के मामले में, पूरे देश में चौथे नम्बर पर आपराधिक क्षेत्र माना जाता है। दिल्ली के एक तरफ उत्तर प्रदेश है, जो यौन अपराधों की राजधानी माना जाता है और एक तरफ हरियाणा आता है, जहां हर दिन अखबार के पन्नों के अंदर, सुर्खियों में रेप के केसेज़ भरे रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था सीधी गृह मंत्रालय के अधीन आती है। गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा जैसे केस, निर्भया जैसे केस, दिल को दहला देते हैं, जिन्होंने सारे हिन्दुस्तान की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। ये केस दिल्ली के अंदर ही हुए हैं और इन केसेज़ की वजह से कहीं न कहीं भारत सरकार को विशेष कानून बनाने पड़े।

महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, Metropolitan City होने की वजह से, यहां की पुलिस को और अधिक चुस्त-दुरुस्त किया जाए, ताकि यहां ऐसे अपराधों में कमी आ सके। दिल्ली के माध्यम से, देश का यह कुरूप चेहरा पुरी दुनिया के सामने उजागर होता है। मैं आपके माध्यम से, देश का यह कुरूप चेहरा पूरी दुनिया के सामने उजागर होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि रेप जैसे जघन्य अपराधों में Juvenile की या minor की उम्र को और कम निर्धारित किया जाए। दूसरा, रेप के विक्टिम को rehabilitation के नाम पर कहीं सिलाई मशीन दी जाती है, कहीं 10,000 रुपये दे दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से अलग-अलग तरह से उन्हें rehabilitate करने की कोशिश की जाती है। इससे उस परिवार के सेंटिमेंट्स पर और जिस बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसके सेंटिमेंट्स पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ता है, हम इस बात का ज़रूर ध्यान रखें।

महोदय, भारत में हर 15 मिनट के अंदर एक बच्चा यौन शोषण का शिकार होता है। आपराधिक रिपोर्ट्स के अनुसार, 2006 में कुल मुकदमें 18,967 थे, जो 2016 में बढ़कर 1,06,958 हो गए। हाल ही में, मानवीय सहायता के लिए फंड मुहैया कराने वाली एक संस्था - World Vision India के एक सर्वे के अनुसार ...**(व्यवधान)**... भारत में हर दूसरा बच्चा किसी न किसी प्रकार से यौन शोषण का शिकार होता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2007 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार 53 परसेंट बच्चे किसी न किसी रूप में यौन शोषण से प्रभावित रहे हैं। यौन शोषण के 90 परसेंट मामले किसी परिचित के द्वारा होते हैं। इन 90 परसेंट मामलों में, परिवार की गरिमा खराब न हो, ऐसे आंकड़े सरकारी रिकॉर्ड तक नहीं पहुंचते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मुकदमों को Fast Track Courts बनाकर सुना जाएसा, क्योंकि ऐसे मामलों

में दोषी कोई घर का व्यक्ति होता है, जो victim को केस withdraw करने के लिए किसी न किसी तरह प्रभावित करता है।...**(व्यवधान)**... महोदय, अंत में मेरे दो सुझाव हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज समाज को सोचना पड़ेगा कि जहां हम सख्त कानून तो बनाएं, Fast Track Courts भी बनाएं, परन्तु इस समस्या का कोई स्थाई समाधान निकालने का प्रयास भी करें। आज समाज में शादी की उम्र बढ़ती जा रही है। युगलों के बीच में आपसी संबंध में ठीक न होने के कारण तलाक के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। सामूहिक परिवार न रहने के कारण तनाव बढ़ता जा रहा है।...**(व्यवधान)**... छोटे परिवारों में तनाव बढ़ता जा रहा है। हमें सोचना होगा कि biological requirement पूरी करने के लिए हिन्दुस्तान में sex market का प्रावधान करना होगा। हमें सोचना होगा कि किस तरह हम गरीब और विशेषकर व्यस्कों के entertainment या मनोरंजन के इंतजाम करें। हमें सोचना होगा कि स्कूलों के माध्यम से good touch and bad touch की शिक्षा कैसे अनिवार्य करनी चाहिए, क्योंकि आजकल दादी और नानी की कहानियां सुनानी हमने बंद कर दी हैं। सब Social media and Whatsapp पर लगे रहते हैं।...**(व्यवधान)**... हमें moral शिक्षा तथा ethical शिक्षा, स्कूलों के माध्यम से देनी होगी, ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार पनप सकें। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार सख्त से सख्त कानून तो बनाए,...**(व्यवधान)**... ताकि हमारा युवा इस रास्ते पर न चले। इस दिशा में सरकार कुछ ठोस उपाय करे, धन्यवाद।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, Sir, straightaway I would like to make three suggestions to the hon. Minister. I request the hon. Minister not to enumerate what is aggravated sexual assault and what is aggravated penetrative sexual assault because when an FIR is filed, the police may file it thinking that it is the penetrative sexual assault but, eventually, after investigation or when the court starts the trial, probably, it may come under the definition of aggravated penetrative sexual assault. Therefore, it is always advisable to leave it to the court, though it is defined. Let the courts decide what penetrative sexual assault is and what aggravated penetrative sexual assault is. This is my first suggestion.

Secondly, I request the hon. Minister to ensure that the special courts are digitalized. In fact, I have gone through the Bill and there is a provision for the special courts. Please ensure digitalization so that the trial could be expedited and justice is done speedily. It will also ensure that the offenders will not repeat the crime. Therefore, modernization is very important.

Thirdly, one of the criminal courts, like the ACB court or CBI special court in every district may be classified as POCSO court also.

In fact, I rise to support the Bill and I sincerely feel that a more draconian law is required because, if you peruse the data, of late, the crime against children have been

[Shri V. Vijayasai Reddy]

consistently rising year after year when compared to 80's and 90's. After 2000, there is a consistent increase in the crime rate, particularly in the Capital city of Delhi. Sir, there are about 1.6 lakh cases of child abuse pending in 29 States plus Union Territories, altogether 31 States. As per the official data available, approximately about 12,609 rape cases were registered under POCSO Act this year itself. Sir, one more point I would like to bring to the notice of hon. Madam. I strongly feel this Amendment further discourages the trend of sexual abuse by acting as a deterrent. That is why I honestly feel that a more draconian law is needed, in the sense that up to ten years in the case of penetrative sexual assault and ten to twenty years for aggravated penetrative sexual assault or death penalty. A more draconian law is required because if you go to the Gulf the crime rate is significantly less because the law is more draconian there. My last point is particularly on some of the cases, being registered, which are of such magnitude that sends shock waves to the collective consciousness of the society. Therefore, I request Madam to make it more draconian and the three suggestions that I have made may be followed by the Minister. Thank you.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, many among us are having a dream of a new India. But, Sir, in this new India, I am sure, Madam Minister also knows that children are being abused like anything. Their lives are being tortured everywhere. It starts from homes, and who are the perpetrators? It is those who are well known to them, those in the families, the surroundings, relatives who are in close contact with the children. They are the perpetrators. Now the Government believes that by deterrence this can be averted and stopped forever. Sir, talking about death penalty, it is part of deterrence, but this Bill will deter whom? Is it the victim or the perpetrator? In many a cases, psychologists say like that, science says like that, technology says like that and in many cases the victims are deterred. That means the perpetrators will go free. The Government may not be aware of this. But please take note of this fact. By passing this legislation India will be part of 13 countries in the world where there is death penalty for child rape. In this modern world of ours, I don't think it is a fair thing for the Indian society. So the Government has to think about it and I earnestly plead that this should be referred to a Select Committee. We support the Bill because we are not for child abuse, not for rape on the child, but stop it. This is not the way. Many friends explained here the figures and the statistics. Sir, certain studies say that out of 100 cases, only 30 are registered. Out of the 30, only three are punished. Sir, this is India. Deterrents will make

it more worse. So, please think in realistic terms. Let the Government understand that this is not the way. Let a committee of concerned people go to the people, the children, the people who are concerned with them and everywhere we can get their opinions collected and we can make this Bill a Bill with real intentions and purposeful deeds. This is my point. Sir, the Law Commission of India has made a study on death penalty. It says, "In focussing on death penalty as the ultimate measure of justice to victims, the restorative and rehabilitative aspects of justice are lost sight of. Reliance on death penalty diverts attention from other problems ailing the criminal justice system such as poor investigation, crime prevention and rights of victims of crime. It is very important. So, death penalty is a great thing for the Government. The country cannot share that view as such.

Sir, children are being abused world-over, because it has become a big industry! Child pornography has become a trillion dollar industry the world-over! The forces behind it are not small. Those forces have political influence. They have trillions of dollars with them. They are the people who are doing this. So, there are no shortcuts to prevent it. It needs a strong political will.

I wish to submit one more thing. We always talk about values. Sir, in this nation of ours 'value' means what? 'Value' means money. In the market economy, 'value' means money. All things are counted only upon money. So, whichever thing yields money, it has a great value. So, if you give money, people will run behind it. That is what is happening, Sir. So, all I say is that the Government should have a political will to stop it. I repeat that the forces behind this are the market forces. ...*(Time-Bell rings)*...

Sir, I conclude with one sentence. My memories go with that small girl in Kathua. She was raped and killed in this country of ours! Sir, I feel ashamed to say when those culprits came out on bail the National Flag was used to welcome them! Is this India, Sir? It is a shameful act. So, I request the Government be dare enough to tell that it is a crime, it is a mistake and it is a wrong-doing.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Please conclude.

SHRI BINOY VISWAM: This is the justice we expect from the Government.

Finally, I repeat once again that this Bill should be referred to a Select Committee. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Now, Shrimati Chhaya. You have six minutes.

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़) : सर, ठीक है, मैं अपनी बात तीन मिनट में खत्म करूंगी। इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं अपनी पार्टी लीडर को धन्यवाद देती हूं।

सर, आज भौतिकता के युग में नैतिकता का पूरी तरह ह्रास हो गया है। कहीं भी हमें सद्भावना, एक-दूसरे के प्रति सम्मान देखने को नहीं मिलता। आज सारा कुछ भौतिकता में समाहित हो गया है। मैं छत्तीसगढ़ अंचल से आती हूं, छत्तीसगढ़ आदिवासियों का प्रदेश है। 'दामिनी' जैसी घटना वहां कई बार देखने को मिली, कई बार सुनने को मिली। पिछले सदन में भी मैंने झलियामारी कांड का उल्लेख किया था। उन सब घटनाओं का मैं यहां पर उल्लेख नहीं करना चाहूंगी कि किस ढंग से एक लड़की महुआ बीनने जाती है और उसके साथ बलात्कार करके, उसकी हत्या करके, उसे नक्सली घोषित कर देते हैं। ऐसी अनेकों घटनाएं हो रही हैं, लेकिन मैं उस घटनाक्रम के पीछे नहीं जाना चाहूंगी। मेरे पास समय बहुत कम है। मैं विषय पर ही बात रखना चाहूंगी। मैडम कठोर कानून बनाने का जो बिल लाई हैं, यह बहु अच्छा है, स्वागतयोग्य है। मैं कहना चाहती हूं कि कानून तो आप बना रहे हैं, विशेष न्यायालय का गठन आप कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश जानता है कि देश में न्यायाधीशों की कितनी कमी है। सामान्य अदालतों में बहुत लंबे-लंबे केसेज़, हजारों-हजारों की संख्या में केसेज़ पड़े हुए हैं। आप विशेष अदालत बनाकर, कितना न्याया कर पाएंगे, यह समय बताएगा। सर, अधिकारियों-कर्मचारियों की भी कमी है, तो जब आप विशेष न्यायालय बनाएंगे, तब इस बात का ध्यान रखें कि उसमें तत्परता से काम हो और सही मायने में बच्चों को न्याय मिले। जहां तक लैंगिक अपराध की बात है, जब हम भारत में चन्द्रयान-2, चन्द्रयान-1 के बारे में देखते हैं, तो हमारा सीना गर्व से फूला नहीं समाता है कि हम उस भारत देश के रहने वाले हैं, लेकिन जब बच्चों के साथ लैंगिक अपराध की घटनाएं उजागर होती हैं, तब शर्म से हमारी नज़र झुक जाती है, हम नज़र उठाकर बात नहीं कर सकते।

सर, आप देख सकते हैं कि विदेशों से भी अनेकों सोशल साइट्स चल रही हैं, जिनके माध्यम से बच्चों को गलत समाचार परोसा जा रहा है। इसको किस कानून और किस नियम के अंदर लाकर, आप कैसे सज़ा देंगे? इसके लिए भी इस नियम में प्रावधान होना चाहिए। सोशल साइट्स के माध्यम से देख-देख कर अनेकों बच्चों ने पिछले दिनों आत्महत्या की है। क्या आप इनको बंद कराएंगे? क्या आप यह कानून में लाकर इसके लिए सज़ा देंगे? यह भी आप इस कानून और इस नियम के तहत लाएंगे, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आज हम देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार की प्रथा खत्म होती जा रही है। पहले घर में चाचा-चाची, दादा-दादी, नाना-नानी सब एक साथ रहते थे, उनके बच्चे रहते थे और सब बच्चे एक साथ खेलते थे। इससे उनमें जागरूकता आती थी और उनका अच्छा ज्ञानवर्धन होता था, लेकिन आजकल एक परिवार हो गया है और सिंगल चाइल्ड, एक बच्चा हो गया है, तो वे बच्चे क्या करेंगे? वे दिन भर मोबाइल से गलत-गलत समाचार और गलत-गलत जानकारी लेते रहते हैं, इसलिए इस पर आप रोक लगाएं। सोशल साइट्स पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है, उस पर रोक लगाना भी बहुत जरूरी है।

मैं कहना चाहूंगी कि जितने भी अपराध हुए हैं, उसका गृह मंत्रालय के पास एक भी आंकड़ा नहीं है। कितने आंकड़े आपके पास आए, कितने आंकड़ों का समाधान हुआ, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को होनी चाहिए। अभी घर-परिवार के बारे में बहुत-से उदाहरण दिए गए। ऐसे कुछ धर्मगुरु भी हैं, जो अभी जेलों में बन्द हैं। उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, वह भी अभी समझ से परे है। ऐसे धर्मगुरु, जो धर्म की आड़ में बच्चों के साथ अपराध करते हैं, उनके ऊपर भी सख्त कानून होना चाहिए। मेरा समय अब खत्म हो रहा है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। उसी टेलीविज़न और वे ही समाचार-माध्यम, जिनमें अश्लीलता परोसी जा रही है, उनमें हम अच्छी-अच्छी चीज़ों के बारे में बताएं और सामाजिक जागरूकता लाएं, तभी हम बच्चों के साथ न्याय कर पाएंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2012 में जो कानून बना, उसके बाद हम सभी जो संशोधन लेकर आए हैं, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि कानून के बनने के बाद उसको लागू करने में जो चार नयी चुनौतियां सामने आई हैं, उन चार चुनौतियों को उन्होंने अपने इस संशोधन के माध्यम से address किया है। पहला विषय है- Child Pornography. अभी हमारे केरल के सांसद भी कह रहे थे और यह सच भी है। जया जी ने भी कहा कि टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है, उसमें अगर यह संगठित अपराध बन रहा है, अगर इसको एक बड़े व्यापार की दृष्टि से प्रायोजित किया जा रहा है, तो इस अवैध व्यापार को चुनौती देते हुए, इसको तोड़ने के लिए इसमें जो Child Pornography की परिभाषा दी गई है, मुझे लगता है कि यह उन अपराधियों को सज़ा दिलाने में सक्षम होगा, जिसकी आवश्यकता हम लोग तेजी से महसूस कर रहे हैं।

दूसरा, केवल ऐसा ही नहीं है, बल्कि जो इस Child Pornography को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो इसको बढ़ा रहे हैं, जो इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, उन लोगों को भी सज़ा देने का इसमें प्रावधान है। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हुईं, जो केवल परिवार, आपसी विषय, मूल्य और नैतिकता तक आई हैं, लेकिन एक संवेदनशील सरकार होने के नाते हमें इस प्रकार के अवैध व्यापारों को और इसे प्रोत्साहित करने वालों को ऐक्ट में सीधे-सीधे परिभाषित करना होगा। माननीय मंत्री जी ने इसे परिभाषित करके दूसरा कार्य किया है, जो आज के समय में बहुत आवश्यक है।

इसका जो तीसरा विषय है, वह यह है कि जो एक हिंसा का वातावरण बनता है और हिंसा - अभी जब सदन में राय चली, मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सब सदस्यों के मन में विषय आया कि चाहे सामुदायिक हिंसा हो, प्राकृतिक आपदा हो या इस प्रकार की कोई परिस्थितियां हों, अगर उस समय किसी बच्चे को अपने लिए कोई सुरक्षा की आवश्यकता हो, उस परिस्थति का अगर कहीं दुरुपयोग किया जाए, तो उसको निश्चित रूप से इसमें परिभाषित किया गया है। मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा कि जैसे ही सदन में एक consensus की राय आई, उन्होंने तुरंत अमेंडमेंट मूव किया, जो हमारी सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

[श्री भूपेन्द्र यादव]

इसका जो चौथा विषय है, वह और ज्यादा खतरनाक है। Child Pornography का विषय है, उसके व्यापार का विषय है, सामुदायिक हिंसा का विषय है, लेकिन चौथा विषय यह है कि बच्चों से इस प्रकार का घिनौना अपराध कराने के लिए जो लोग उनके हार्मोन्स को अप्राकृतिक रूप से विकसित करने के लिए कैमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं, ड्रग्स का प्रयोग कर रहे हैं, मेरा मानना है कि उसके संबंध में जो यह संशोधन लाया गया है और इस प्रकार के लोगों के लिए जो सख्त सज़ा का प्रावधान किया गया है, वह बहुत जरूरी है, टाइम पर उठाया गया कदम है, जिसको आगे बढ़ाना चाहिए। कुल मिलाकर इस संशोधन में इन 4 विषयों को address किया गया है। बहुत सारे सदस्यों को लगता है और पूरी दुनिया में एक बहस चलती है कि जो capital punishment का विषय है, जो मृत्यु दण्ड का विषय है, उसका कुल मिलाकर संतुलन किस प्रकार का हो? लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि बचपन में इस प्रकार के अपराध के साथ जो victim बनेगा, जो इस प्रकार की हिंसा का victim बनेगा और इसलिए इस बिल के object में भी जब लिखा गया है कि यह सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से पूरे के पूरे आने वाले समाज के भविष्य को तोड़ना चाहता है।

महोदय, इन 4 संशोधनों में सरकार जिस प्रकार के संशोधन लायी है, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ... जैसा अमी यज्ञिक जी भी कह रही थीं कि एक्ट में बाकी सारे प्रोविजंस हैं, माननीय मंत्री जी भी सदन में यह बताना चाहेंगी कि यह जो एक्ट है, इसको कितनी तेज़ी से सरकार लागू कर रही है, निश्चित रूप से हमें उनके संबोधन में सुनने को मिलेगा, लेकिन ये जो चार चुनौतियां हैं, ये ऐसी चुनौतियां हैं, जिन्हें किसी Select Committee के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इस सदन को अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले समाज के लिए, उनके भविष्य के लिए और जो लोग असंगठित तरीके से इस तरह के अपराध कर रहे हैं, उनके खिलाफ एकमत होकर इन चारों संशोधनों को स्वीकार करना चाहिए।

महोदय, बच्चों के खिलाफ जो हिंसा है, इसमें लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं होना चाहिए। अभी ये आंकड़े भी देखने में आ रहे हैं कि लड़कों के प्रति जो इस प्रकार के अपराध होते हैं... जया जी ने बिल्कुल सही कहा कि उनके बारे में जानकारियां कम दी जाती हैं। इसमें कभी घबराना नहीं चाहिए, यदि आंकड़े बढ़ते हैं तो बढ़ें, लेकिन कम से कम हमें यह नहीं कहना चाहिए कि आंकड़े बढ़ गए। कई बार आंकड़े इसलिए बढ़ जाते हैं कि समाज में एक प्रकार की भावना रहती है, हमें दूसरी तरफ से जाना चाहिए कि जिसके खिलाफ अपराध हुआ है, उसका प्रकटीकरण समय पर होना चाहिए, उसकी संरक्षा समय पर होनी चाहिए, उसको इमोश्नल protection व अन्य protection समय पर देनी चाहिए। एक अच्छे कवि हैं 'इब्न-ए-इंशा'। उन्होंने बचपन को लेकर बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी थीं। इब्न-ए-इशा ने दो पैराग्राफ में अपनी बातें कहीं थी कि बचपन में कैसे थे और आज कैसे थे। उनकी पहली चार पंक्तियां हैं-

"मैं छोटा सा लड़का था उन दिनों
मेले में पहुंचा हुमकता हुआ

जी मचलने लगा एक-एक शय पर

लौट आया, लिए हसरतें सैकड़ों
मैं छोटा सा लड़का था उन दिनों"

लेकिन जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो आगे लिखते हैं-

"आज मेला लगा है उसी शान से

आज चाहूं तो एक-एक दुकान ले लूं
आज चाहूं तो सारा जहां ले लूं

नारसाई का जी में अब धड़का कहां है
पर वो छोटा, सा भोला सा लड़का कहां है?"

महोदय, वक्त बदलता है और वक्त बदलने के साथ जो अपना बचपन चला जाता है, बचपन में जिसके ऊपर अत्याचार होता है, बचपन में जब यौन हिंसा का victim बनता है, बचपन में जिसको इस प्रकार के drugs दिए जाते हैं, बचपन में जिसके साथ इस प्रकार की pornography होती है, यह देश के भविष्य को बरबाद करने वाले जो लोग हैं, इनके खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कानून आना चाहिए। सरकार ने समय पर इस संवेदनशील विषय को उठाया है, इस पर कदम उठाए गए हैं। इस पर ने केवल सरकार ने चारों विषयों को परिभाषित किया है, बल्कि इसके साथ ही साथ कड़ी सज़ा के प्रावधान भी लाए हैं। मैं सदन से आग्रह करूंगा कि इस संवेदनशील विषय को हम एकमत होकर पारित करें और बच्चों के खिलाफ जो हिंसा हो रही हैं, उसके खिलाफ रोकथाम लगाने के लिए समाज में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जागरूकता का कार्य हम सब मिलकर करें, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): The hon. Minister to reply.

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT; AND THE MINISTERY OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, 28 hon. Members of Parliament today spoke on the Amendments proposed by our Government. I, at the onset, express my gratitude especially for the passion with which they spoke. I join cause with their angst and anxiety with regard to certain elements of implementation and a desire to render justice to our children. I take a special moment, Sir, with your permission and the permission of the House to reflect on a confession by a colleague in this House today.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA) *in the Chair*]

He shared with the House, and, through this House, with the country, how he faced sexual abuse at the age of 12. The fact that he recounts it today at the age of 58, 46 years later, tells us what kind of an imprint sexual abuse or assault leaves on a

[Shrimati Smriti Zubin Irani]

child and as an adult how many memories then of that abuse or assault we carry for the rest of our lives. So, as a colleague, especially given, as Bhupender Yadavji said, it is difficult for men to come out after accepting that such an abuse has taken place with them to publicly proclaim that 'Yes, they too can be victims of sexual abuse and sexual assault.' So, I am sure, the House will join me in applauding the courage of our colleague, Derek O'Brienji, who 46 years later speaks of his abuse not only to reflect on the amendments proposed but as a man telling the country that if you are victims, keep quiet no more.

Sir, many hon. Members participated in this discussion, and I would like to name all the hon. MPs who spoke. Initiated by Vivekji, we received views of Harnathji, Vijilaji, Abir Ranjan Biswasji, Jaya Bachchanji, Sarojiniji, Kahkashanji, Lingaiahji, Jharnaji, Manojji, Amee Yajnikji, Derek O'Brienji, Vandana Chavanji, Rajaramji, Sushil Kumar Guptaji, Vijayasai Reddyji, Binoy Viswamji, Chhayaji, Bhupender Yadavji along with Narendra Jadhavji, Shamsherji, Ravi Prakashji, Sasmit Patraji -- his first speech and I applaud him that as a parent and as a Member of Parliament this is the Bill on which you chose to speak; I will buy it for a few minutes -- Nazir Amhedji, who is passionate about the view as a representative of the State of Jammu and Kashmir, Ravindra Kumarji, Kantaji. Elangovanji, in his speech, particularly asked why is it that we deem fit to describe acts perpetrated against our children only in violent circumstances or in circumstances of natural calamity leaving out the word 'communal' or 'sectarian'. This is a concern or a question posed by many Members. Taking a sense of the House in its spirit of cooperation that I witnessed today in this very House, I conceded that let me now bring a reflection upon the sense of the House and bring about an amendment in such a short while. This is a reflection of my gratitude and that of the Government for the solidarity shown by all political parties in supporting this particular Amendment that I have presented today in this august House.

Vivekji is right in his observation, Sir, and what we touch upon today is just a tip of the iceberg. True, for it is the tip of the iceberg, many cases swept under the carpet, many cases not spoken about, as Derekji said, because the perpetrator happens to be known to the victim or happens to be a part of the victim's family. As has been said even by Jaya Bachchanji for how long do we wait for justice to be dispensed. Recognizing the fact that justice delayed is justice denied, the Government, under the leadership of Shri Narendra Modi, has sanctioned 1,023 fast track courts, particularly, to be made for

dispensing cases which are pending under POCSO and those women who are raped. I must here, through you, Sir, share with the

House that when the Government took cognizance of pending cases, we saw the cases in various High Courts and came to the conclusion that 1,66,882 cases were pending across the country. The Government reached out to each State, and I can share this with the House, Sir, that 18 States have consented to set up this court. In collaboration with the Ministry of Law and Justice and Home Affairs Ministry, we have ensured that expenditure of ₹767 crores, of which the Government of India support will be Rs. 474 crores, is now given so that these fast track courts are established within the limited time period of 2019-20 to 2020-21. Sir, the fact that the Government has impressed upon every State, and across all Ministries, that the establishment of these 1,023 fast-track courts in the country would be done within one financial year, reflects the priority that the Government gives to ensuring that justice is delivered to every child victim in our country.

There are many distinguished parliamentarians who reflected on how we keep a track of the status of the pendency of cases. I would like to add here that given the directive by the Government of India to set up these 1,023 special fast-track courts, we are also going to ensure that every quarter, from the Registrar General of every High Court, we look at the progress made, including the utilization of funds, and these reports then would be shared through the Department of Law and Justice with the Ministry of Home Affairs and my Ministry, the Ministry of Women and Child Development. At the end of the day, to ensure what was the quality of justice that was dispensed, an evaluation would be done through an institution empanelled by the NITI Aayog with regard to this particular process, which the Government is about to undertake.

Sir, here I would like to address a concern by Vandanaji who asked whether a Sessions Court would convert one day of its functioning into a fast-track court. Through you, Sir, I would like to inform her that this particular facility that the Government of India seeks to now dispense in the rest of the country would be in addition to the existing Sessions Courts.

Sir, there are some Members who highlighted the cognizance taken by the hon. Supreme Court of India with regard to the pendency of cases related to POCSO. I would like to tell the hon. House that my Ministry officials recently had a meeting, post this *suo motu* cognizance taken by the hon. Supreme Court, with the Registrar of the

[Shrimati Smriti Zubin Irani]

Supreme Court so that we can see how to strengthen dispensation of justice. In our conversation with the Registrar of the Supreme Court, we have reflected on the need to capture data. We have also reflected on the need for strengthening facilities through forensic science laboratories. We have also seen how to strengthen and give an extra impetus to the National Commission for Protection of Child Rights with regard to these cases. This being said, Sir, I would like to highlight the fact, and we all know, that the monitoring of the implementation of the Act falls within the ambit of the NCPCR and, through the NCPCR, even the States. The State Commission for Protection of Child Rights has to address State-specific issues. Through the Ministry, Sir, we have requested all States to appoint a senior nodal police officer in every State and Union Territory. I am happy to share with the House, Sir, that the same has been complied with by all States concerned. Now, given that implementation of the Act and issues of law and order fall within the ambit of the State, through the aegis of the Ministry of Home Affairs, what are the steps that have been undertaken by the Modi Government to facilitate justice for victims? There are some Members like Vivekji, Vandanaji and others who had spoken about the lack of data from NCRB post 2016. I am informed by the officers who serve NCRB that earlier cases did not make a referral to the gender of the victim. Hence, to refine the data now, the States are being implored to ensure that a distinction in terms of gender can be made between a male victim and a female victim, so that in terms of rehabilitation and other support facilities given to that victim, we can refine our rehabilitation processes as well. But I must say, Sir, in the year 2019, in the month of February, the Ministry of Home Affairs launched a special online analytical portal called the Investigation Tracking System for Sexual Offences under which policy data used by law enforcement officers helped the States to monitor pendency of such cases at the level of police stations. Hence, we are going down to the detail in terms of the local police station to track pendency at the stage of investigation because the Act itself provides for investigation to be completed within a given time frame. I remember, Sir, I spoke on this particular law seven years ago in this very House and, at that time, I spoke about the need for a national database on sexual offenders. I must here, Sir, congratulate and give thanks to our hon. Prime Minister because the Ministry of Home Affairs launched the National Database on Sexual Offenders on the 20th of September, 2018. Regrettably, let me share the number today of the National Database on Sexual Offenders. As of this day, I am informed by the officers of the Ministry of Home Affairs that the

database contains data on 6,20,000 sexual offenders in our country. It facilitates law enforcement agencies in order to track the movement of such people, especially when they go for employment in some institution and the institution undertakes an employee's verification with the local police station. Some Members spoke about forensic labs. I would, through you, Sir, like to tell the hon. Members that currently, under the Ministry of Home Affairs, in the Central Forensic Science Laboratory, we have seven labs functional; State Forensic Science Labs are 32 in number and Regional Forensic Science Labs are 75 in number. However, regarding the quality of our interaction with forensic science labs in terms of investigation, in terms of how medical officers should act when compiling this data or collecting evidence, the Ministry of Home Affairs has notified guidelines for collection of forensic evidence in sexual assault cases and even standardised the composition of sexual assault forensic kits. I would, through you, Sir, like to tell the hon. House and our hon. Members that the Ministry of Home Affairs has initiated training and skill-building programmes for not only investigative officers but also prosecution officers and medical officers. And till now, Sir, the Ministry of Home Affairs has shared with us that 2,575 officers have been trained in collection handling and transportation of forensic evidence and 3,120 sexual assault evidence collection kits have been made a part of this orientation training within the States. Sir, our hon. Member, Shri Vijayasai Reddy, said, why would you go into a description of penetrative assault. There was a presumption under law -- and my apologies to the House for being a bit crude in my description given; there is a compulsion under law to explain this -- that penetrative sexual assault will only be an assault where penetration is done by the individual concerned. But there are also reports of various objects being inserted into children like glass bottles, pencils and other instruments. If we do not have the definition cover these objects, then, in some way, we disabilitate investigative officers and prosecution officers. Sir, my colleague, Prof. Manoj Jha, who is not in the House right now, reflected heavily on the death penalty, but then was kind enough to correct himself that death penalty is just an option given under the Amendments moved. The punishment now goes from twenty years till the entire life or death, as may be deemed fit by the Court. Given that the Courts wisely use these kinds of descriptive punishments as has been concluded upon by Parliament, I am sure that we can rely on the wisdom of the Courts to use the death penalty in the rarest of rare cases or as the Court may deem fit given the case before them. There are some Members who were a bit concerned about specific timelines given within which trials have to be completed, within which FIRs have

[Shrimati Smriti Zubin Irani]

to be registered. I would like to tell them that most of it is already provided for in the Act. In terms of the entire trial to be completed, it is to be completed within one year. In terms of investigation to be completed under, in fact, CrPC (Amendment) Law, 2018, it is to be completed within two months from the filing of the FIR. In respect of charge sheet also, from the date of charge sheet, two months for trials. This is already provided for in the law. Our distinguished colleagues spoke about the need to look at institutional homes. In fact, one of our colleagues spoke about, 'what happens when children who are brought to a remand home or an institutional home, much more beyond the age of 18, I have through my office, communicated with every Chief Minister across the country to take cognizance of the challenges in institutional care homes. And, the JJ Act and otherwise, the law provides for them to be shifted out and then consequently also be rehabilitated. I am sure that the hon. Chief Ministers across the country will also look at this particular ambit which is already provided in the law. There are many hon. MPs who spoke about how do we, through our Ministry, help, support children in terms of rehabilitation. We have implemented the Child Protection Service Scheme in conjunction with States and Union Territories. Through you, Sir, I would like to tell the House that we are supporting approximately 75,000 children across 2,000 child care institutions through this Child Protection Service Scheme. While, I introduced this Bill for the consideration of the entire House, I spoke about a case from Yadadri. Many people wonder whether our children are aware enough to use these facilities that are being provided by the NCPCR and other establishments. The case that I presented to the House, the eight year old called up the Childline Help No. 1098 to get the requisite help from the State Government and the local police station. I must also here, share with you that NCPCR has ensured that we share with every Chief Secretary, every DG, every District Magistrate and every SP across all States, the guidelines for implementation of the Act, the legal tool kit for cyber crime, the user handbook of the Act and the Do's and Dont's relating to safety on internet with regard to children. But, Tankhaji spoke about the challenges that accrue from children in schools. I would like, through you, to tell the hon. Member that under the HRD Ministry, under the Samagra Shiksha Programme, 42 lakh Government elementary teachers, which include head teachers, head masters and others will be trained in this particular year with regard to not only the provision of POCSO Act but also the JJ Act and school safety guidelines. Now, through this training, it will become compulsory for every school to display a board on safety

6.00 P.M.

with helpline and emergency numbers and the name of the contact person concerned. Through you, Sir, I would like to tell the hon. Members that I personally held a meeting with the hon. Minister of HRD to see as to how we can increase our efficacy in engaging with schools with regard to child safety, and, while not limit ourselves to school, also look at institutions of higher education. I have been assured by the hon. Minister, HRD that in conjunction with CBSE and State Boards, not only will we look aggressively at school safety guidelines but also some Members suggested good touch, bad touch classes within the school premises. That is also a proposal that has been discussed already with the Minister of HRD. Mr. Biswas spoke about the issue of consent. Before I end my speech, Sir, I would like to respond to two points.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Just a minute Madam. The House will sit beyond 6 o'clock till the disposal of this Bill and the Special Mentions. Now, please continue.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I will just take last two points. A point was raised about consent, consensual sex between children who are below the age of 18 and above the age of 16. The hon. Member also made a mention about the relationship between a man and his wife under the age of 18 years. I would like to say here that the Supreme Court has reflected on it in light of the POCSO provisions and finds this particular aspect void *ab initio*. In fact, यह शुरू से ही निष्क्रिय है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह हो ही नहीं सकता। दूसरे, age of consent की दृष्टि से जो चर्चा हुई, इसी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने एडवाइज़ किया था कि इसे कम न किया जाए। यह चर्चा पहले भी हो चुकी है और इस चर्चा के चलते, the wisdom of both the Houses and the Standing Committee reflects in the position that we have taken today.

Sir, I conclude with gratitude to all the hon. Members. Tankhaji made a mention of special children that even he seeks to serve through the school that he runs and through other NGOs. Sir, I am cognizant of the fact that even though the law provides for counseling, even though the law provides for translators, even though the law provides for support to the victim, especially if it is a *divyang* victim, there might be gaps that fall between conversations intra-State. It is my intention to call for a special meeting with all the States concerned with regard to POCSO and its implementation, which will also provide a discussion on mental health and support through counsellors. I have extended the need to get help from the Ministry of Health and institutions like

[Shrimati Smriti Zubin Irani]

NIMHANS and AIIMS, so that institutions, that work, in their capacity to engage with counsellors, can also aid the Government in this interaction with the State and can help us outline, possibly through even Central Social Welfare Board or State Social Welfare Board, the counsellors that are already registered so that they can be used to help the children concerned.

Sir, today, many hon. Members mentioned about how many stakeholders were spoken to. While there are many stakeholders who were spoken to, including people who work as social activists in conjunction with the Government or without it, I can say here, as I end my speech, that I personally also had interaction with regard to protection of our children, with the Nobel laureate as celebrated as Kailashji.

So, Sir, I again take this opportunity for the humaneness that this House has shown and the support that this House has shown. Not only as a Minister but also as a former Member of this House, let me, Sir, through you, convey my grateful thanks to all the hon. Members.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, the question is:

That the Bill further to amend the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, we shall take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): In Clause 3, there is one Amendment (No.1) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is not present.

Clause 3 was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): In Clause 4, there is one Amendment (No.5) by the hon. Minister, Shrimati Smriti Zubin Irani.

CLAUSE 4 - AMENDMENT OF SECTION 5

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, this is the Amendment that the House felt should happen and I have conceded to the will of the House. I move:

5. That at page 2, *for* lines 23 and 24, the following be *substituted,* namely:

"(II) in clause (s), for the words "communal or sectarian violence", the words "communal or sectarian violence or during any natural calamity or in similar situations" shall be substituted."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): In Clause 5, there is one Amendment (No.2) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is not present.

Clause 5 was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): In Clause 6, there is one Amendment (No. 6) by Shrimati Smriti Zubin Irani.

CLAUSE 6- AMENDMENT OF SECTION 9

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I move:

(6) That at page 2, *for* lines 34 to 36, the following be *substituted,* namely: "(i) in clause(s), for the words "communal or sectarian violence", the words "communal or sectarian violence or during any natural calamity or in similar situations" shall be substituted;"

The question was put and the motion was adopted

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

Clause 7 was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): In Clause 8, there are two Amendments (Nos. 3 and 4) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is not present.

Clause 8 was added to the Bill.

Clauses 9 to 11 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.